आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 18 लखनऊ, शुक्रवार 14 अगस्त 2026 सा 20 अगस्त 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली। लोकसभा की कार्यवाही बृहस्पतिवार को अनिश्चिकाल के लिए स्थगित कर दी गई और मॉनसून सत्र में निचले सदन की कार्य उत्पादकता १६ प्रतिशत रही, वहीं इस बार एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के कारण लोकसभा में लगातार गतिरोध बना रहा। इसे दूर करने के लिए विपक्ष एवं सत्ता पक्ष के बीच आज तक सहमति नहीं बन पाई। मानसून सत्र के दौरान केवल २८ और २९ जुलाई के दौरान सदन में सामान्य माहौल देखने को मिला जब लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, २०२६' पर लगभग दस घंटे तक चर्चा हुई। मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन की कार्यवाही ११ बजे आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि, सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम् से पहले वह अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम् के सभी छह अंतरों के गायन की रिकार्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। हालांकि, कार्यवाही स्थगित होने के बाद अपने संवाददाता सम्मेलन में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बताया कि इस सत्र में लोकसभा की कार्य उत्पादकता १६ प्रतिशत रही। संसद का वर्तमान मानसून सत्र २० जुलाई को आरंभ हुआ था। सरकार ने कहा था कि वह छात्रों के विषय पर चर्चा कराने और इस पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के लिए तैयार है, हालांकि विपक्ष का कहना था कि राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा, छात्रों पर कार्रवाई को लेकर शाह के जवाब और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से माफी की मांग करने के मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा वह इन तीनों मांगों पर कायम है। लोकसभा अध्यक्ष पूरे सत्र में विपक्षी सदस्यों से बार–बार प्रश्नकाल

चलने देने, विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने और कार्यवाही में सहयोग करने की अपील करते रहे, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। सत्र के आखिरी दिन तक यह गतिरोध नहीं टूट सका। सदन ने नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में २६ जुलाई को परीक्षा में सुधार से संबंधित 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, २०२६' को मंजूरी दी। लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, २०२४ में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विधेयक पर हुई चर्चा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, पार्टी नेता गौरव गोगोई, भाजपा के तेजस्वी सूर्या, बांसुरी स्वराज, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी, द्रमुक के सांसद दयानिधि मारन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) की नेता सुप्रिया सुले आदि ने भाग लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया। सदन ने राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के गायन को अनिवार्य बनाने वाले 'राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, २०२६' को भी द्रमुक समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। सदन में इनके अलावा अन्य कुछ विधेयक विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच चर्चा के बिना पारित किए गए। इनमें 'उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, २०२६', 'विनियोग (संख्यांक ३) विधेयक, २०२६', 'न्यायाधिकरण सुधार विधेयक, २०२६', 'कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक, २०२६', 'जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, २०२६' और 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, २०२६' शामिल हैं। सदन ने 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, २०२६', 'बैंककार बही साक्ष्य विधेयक, २०२६', 'भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, २०२६', 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, २०२६' और 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, २०२६' को भी हंगामे के बीच ही चर्चा के बिना पारित किया।सदन में कई विपक्षी दलों की आलोचना और विभिन्न परमार्थ संगठनों की मांग के बाद बुधवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन (एफसीआरए) विधेयक, २०२६ को विस्तृत समीक्षा और संभावित सुझावों के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया।

अंतर्जनपदीय तबादले में मनचाहे स्कूल की तैनाती का दावा नहीं कर सकते शिक्षक

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की मांग करने वाले प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक किसी विशेष विद्यालय में तैनाती दिए जाने का अधिकार नहीं जता सकते। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति के तहत ऐसे मामलों पर जिलेवार विचार किया जाना है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने चार शिक्षकों की ओर से दाखिल रिट याचिका खारिज करते हुए जून २०२६ में जारी प्रदेश सरकार की स्थानांतरण नीति को सही ठहराया। याचिकाकर्ताओं ने २२ जून, २०२६ के शासनादेश में स्थानांतरण के लिए निर्धारित जिलेवार छात्र–शिक्षक अनुपात (पीटीआर) को चुनौती दी थी। शिक्षकों की दलील थी कि पीटीआर की गणना जिलेवार के बजाय विद्यालयवार और कक्षावार की जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि नीति के तहत अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के मामलों पर जिलेवार आधार पर विचार किया जाना है। याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) (तैनाती) नियमावली, २००८ के तहत विशेष जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी। इन नियमों में निर्धारित परिस्थितियों को छोड़कर स्थानांतरण पर रोक का प्रावधान है। राज्य सरकार ने चार जून, २०२६ को नई स्थानांतरण नीति जारी कर निर्धारित श्रेणियों में अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति दी थी। इनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जहां पति–पत्नी अलग–अलग जिलों में तैनात हैं। नीति के अनुसार, यदि पति और पत्नी दोनों प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक हैं तो कम छात्र–शिक्षक अनुपात वाले जिले में स्थानांतरण के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है। अदालत ने इस व्यवस्था को शिक्षा के अधिकार कानून के विपरीत मानने से भी इनकार कर दिया। इस फैसले से स्पष्ट है कि पात्र शिक्षक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट विद्यालय में तैनाती को अपना अधिकार नहीं बता सकते।

पूर्व मंत्री अनंत कुमार मिश्रा बसपा से निष्कासित

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अंटू मिश्रा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में बृहस्पतिवार को दल से निष्कासित कर दिया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर इस संबंध में ऐलान करते हुए कहा उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनंत कुमार मिश्रा उर्फ अन्टू मिश्रा को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों आदि के फलस्वरूप आज तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा राज्य में चुनावी माहौल के बीच पार्टी के सभी स्तर के लोग अपने विरोधियों के तमाम हथकंडों से सावधान रहते हुए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ बसपा के आंबेडकरवादी मिशन को आगामी विधानसभा चुनाव में सफल बनाने में पूरे जी जान से जुटे रहें। ''अनंत कुमार मिश्रा २००७ में बनी बसपा की पूर्ववर्ती सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री थे। मायावती ने इससे पहले अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ और पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू–कश्मीर में पार्टी के समन्वयक रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में दल से निष्कासित कर दिया था।

सम्पादकीय

अडानी मामले में अमेरिकी न्याय विभाग पर उठे गंभीर सवाल

अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गरौफिस ने अडानी समूह के खिलाफ घूस और धोखाधड़ी से जुड़े आपराधिक मुकदमे को खारिज करने पर सहमति दे दी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि संघीय अभियोजकों के किसी मामले को वापस लेने के फैसले की समीक्षा करने का न्यायाधीश का अधिकार सीमित होता है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोग खारिज करने के निर्णय में अपनाई गई प्रक्रिया में ऐसी "अनियमितताएं" थीं, जो चिंताजनक हैं। न्यायाधीश की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला केवल अडानी समूह के खिलाफ आरोपों के खत्म होने तक सीमित नहीं है। उनके आदेश से अमेरिकी न्याय व्यवस्था में अभियोजन संबंधी निर्णयों की पारदर्शिता और उन पर राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव की संभावनाओं को लेकर भी सवाल उठते हैं। न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि न्याय विभाग ने इस मामले में सामान्य प्रक्रिया से हटकर कदम उठाया। उन्होंने विशेष रूप से न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ट्रेंट मैक्कॉटर की भूमिका पर सवाल उठाया। न्यायाधीश के अनुसार, मैक्कॉटर ने विभिन्न संघीय कार्यालयों के अनेक अधिकारियों और विशेषज्ञों की पेशेवर राय को नजरअंदाज किया। इससे भी अधिक गंभीर बात यह बताई गई कि मामला वापस लेने का निर्णय अडानी के वकीलों के साथ मिलकर लिया गया, जबकि अमेरिकी जांच एजेंसियोंएफबीआई और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी)के साथ–साथ मामले की जांच करने वाले अभियोजकों और अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय की सलाह नहीं ली गई। न्यायाधीश ने इस प्रक्रिया को "अत्यंत असामान्य" बताया। इससे पहले भी जब न्याय विभाग ने मुकदमा वापस लेने का प्रारंभिक अनुरोध किया था, तब अदालत ने उसके तर्कों को "कमजोर, सतही और अस्पष्ट" बताया था और मामले को खारिज करने के ठोस कारण बताने को कहा था। अब अंतिम निर्णय में न्यायाधीश की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि न्याय विभाग अदालत को पूरी तरह संतुष्ट करने में सफल नहीं रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन परिस्थितियों में अमेरिकी न्याय विभाग इस मामले को समाप्त करने पर सहमत हुआ। न्यायाधीश के अनुसार, विभाग यह स्पष्ट नहीं कर सका कि अडानी पक्ष किन शर्तों पर सहमत हुआ और उसके बाद ट्रंप प्रशासन ने अभियोग वापस लेने का निर्णय क्यों लिया। यदि किसी गंभीर आपराधिक मामले को अचानक समाप्त किया जाता है तो उसके पीछे की प्रक्रिया और आधार सार्वजनिक रूप से स्पष्ट होना चाहिए। न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता का महत्व इसी कारण है। इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा दर्ज मामले में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी द्वारा क्रमशः ६० लाख और एक करोड़ २० लाख डॉलर के भुगतान पर सहमत होने की बात सामने आई थी। ऐसे में आपराधिक मुकदमे का खारिज होना इस धारणा को मजबूत कर सकता है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोगों के लिए कानूनी प्रक्रिया के परिणाम आम लोगों से अलग हो सकते हैं। हालांकि केवल भुगतान या समझौते को सीधे "बरी" होने के बराबर मानना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा, लेकिन न्यायाधीश की टिप्पणियां निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका की न्याय व्यवस्था को लंबे समय से संस्थागत स्वतंत्रता और कानून के शासन की मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। यदि वहां का एक न्यायाधीश स्वयं अभियोजन प्रक्रिया में असामान्यताओं और अनियमितताओं पर सवाल उठाता है, तो इसे सामान्य प्रशासनिक टिप्पणी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप प्रशासन के दौर में अमेरिकी संस्थाओं के कामकाज को लेकर अनेक बहसें सामने आई हैं। अडानी मामले में भी यही सवाल उठता है कि क्या सत्ता और प्रभावशाली कारोबारी हितों के बीच दूरी बनाए रखने के लिए पर्याप्त संस्थागत सुरक्षा मौजूद है। लोकतंत्र में कानून की विश्वसनीयता केवल इस बात से तय नहीं होती कि मुकदमा अदालत तक पहुंचा या नहीं, बल्कि इससे भी तय होती है कि कानून सबके लिए समान रूप से और पारदर्शी ढंग से लागू हुआ या नहीं। अडानी प्रकरण का अंतिम निष्कर्ष जो भी हो, इस मामले ने अमेरिकी न्याय प्रणाली की कार्यप्रणाली पर एक महत्वपूर्ण बहस जरूर छेड़ दी है। अदालत द्वारा अभियोग खारिज करने की अनुमति दिए जाने के बावजूद न्यायाधीश की तीखी टिप्पणियां यह संकेत देती हैं कि प्रक्रिया को लेकर उनके मन में गंभीर असंतोष था। सवाल केवल यह नहीं है कि अडानी समूह के खिलाफ मुकदमा क्यों खत्म हुआ, बल्कि यह भी है कि मुकदमा खत्म करने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी, स्वतंत्र और न्यायसंगत थी। यही इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सबक है। न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता धन, सत्ता या प्रभाव से नहीं, बल्कि समानता और पारदर्शिता से कायम रहती है। यदि प्रभावशाली लोगों के मामलों में सामान्य प्रक्रिया से अलग रास्ता अपनाए जाने की धारणा मजबूत होती है, तो इसका नुकसान केवल किसी एक मुकदमे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था की साख पर पड़ता है। अडानी मामले में अमेरिकी न्यायाधीश की टिप्पणियां इसी व्यापक चिंता को सामने लाती हैं।

खनिज अधिकारों पर केंद्र की पहल संघीय ढांचे के लिए गंभीर सवाल

राकेश पाण्डेय 'निश्छल'

खनिज संसाधनों पर राज्यों के अधिकार सीमित करने की केंद्र की पहल ने एक बार फिर भारतीय संघीय व्यवस्था, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता और न्यायपालिका के निर्णयों के सम्मान को लेकर गंभीर बहस खड़ी कर दी है। केंद्र सरकार ने संसद में 'खदान एवं खनिज पदार्थ (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक–२०२६' पेश किया है। प्रस्तावित कानून के प्रभावी होने के बाद राज्यों को खनिज पट्टों अथवा खनिज–युक्त भूमि पर रॉयल्टी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का टैक्स या उपकर लगाने का अधिकार नहीं रहेगा। खनिज की मात्रा, उसके मूल्य अथवा रॉयल्टी को आधार बनाकर अतिरिक्त कर लगाने की राज्यों की शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। पहली नजर में यह पहल खनन क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश के रूप में देखी जा सकती है। केंद्र सरकार का तर्क है कि खनन उद्योग पर करों और विभिन्न शुल्कों का बोझ अधिक होने के कारण पिछले एक दशक में किए गए अनेक सुधारों के बावजूद इस क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। उद्योग जगत भी लंबे समय से यह दलील देता रहा है कि भारत में खनिज क्षेत्र पर कराधान का स्तर दुनिया के कई देशों की तुलना में काफी अधिक है। यदि करों का अत्यधिक बोझ निवेश, उत्पादन और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित कर रहा है तो उस पर विचार होना ही चाहिए। खनन क्षेत्र में निवेश बढ़े, प्रक्रियाएं सरल हों और देश के प्रों तिक संसाधनों का बेहतर उपयोग हो, यह व्यापक राष्ट्रीय हित का विषय है। लेकिन सवाल केवल खनन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता का नहीं है। असली प्रश्न यह है कि प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को किस सीमा तक सीमित किया जा सकता है और वह भी किस प्रक्रिया के तहत। भारत का संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन पर आधारित है। खनिज संपदा का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिंदा राज्यों में केंद्रित है और इन राज्यों के लिए खनिज केवल औद्योगिक विकास का साधन नहीं, बल्कि राजस्व का भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐसे में राज्यों को अतिरिक्त कर या उपकर लगाने के अधिकार से पूरी तरह वंचित करना उनके वित्तीय अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाला बड़ा कदम है। इस प्रस्तावित बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक पहलू यह है कि इसके जरिए उस न्यायिक व्याख्या को निष्प्रभावी करने का प्रयास दिखाई देता है, जिसके तहत २०२४ में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने खनिज–समृद्ध राज्यों के अधिकारों की पुष्टि की थी।संविधान पीठ ने खनिज–युक्त भूमि पर राज्यों के स्वतंत्र कराधान अधिकार को मान्यता दी थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन जब किसी कानून का उद्देश्य किसी न्यायिक निर्णय की मूल संवैधानिक व्याख्या को प्रभावहीन करना हो, तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या इस कदम के संवैधानिक और संघीय प्रभावों पर पर्याप्त विचार किया गया है। न्यायपालिका के निर्णयों को संसद कानून बनाकर अप्रासंगिक कर सकती है, लेकिन किसी न्यायिक निर्णय को सीधे पलटने की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच संतुलन के लिए सहज नहीं मानी जा सकती। संसद और न्यायपालिका के अपने–अपने संवैधानिक दायरे हैं। इसलिए ऐसे किसी भी कानून में यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह न्यायिक निर्णय के आधारभूत संवैधानिक सिद्धांत को समाप्त कर रहा है या केवल उस निर्णय से उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कर रहा है। यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, केंद्र और राज्यों के बीच कराधिकार का सवाल केवल राजस्व का सवाल नहीं है। यह भारतीय संघीय व्यवस्था में राज्यों की भूमिका और उनकी स्वायत्तता से जुड़ा विषय है। जिन राज्यों में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर और अन्य महत्वपूर्ण खनिज प्रचुर मात्रा में हैं, वहां खनन से पर्यावरणीय दबाव, विस्थापन, बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त बोझ और स्थानीय स्तर पर अनेक सामाजिक–आर्थिक समस्याएं भी पैदा होती हैं। ऐसे में यदि राज्य खनिज संसाधनों से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे केवल अधिक कर वसूलने की मंशा नहीं, बल्कि संसाधन–संपन्न क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने का तर्क भी हो सकता है। यहां केंद्र सरकार की उस दलील पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि अलग–अलग राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त कर खनन क्षेत्र के लिए लागत बढ़ाते हैं और निवेश को हतोत्साहित करते हैं। यदि ऐसा है तो समस्या का समाधान राज्यों के अधिकार पूरी तरह खत्म करने के बजाय कराधान की अधिकतम सीमा, समान मानक या समन्वित व्यवस्था बनाकर भी किया जा सकता है। केंद्र और राज्यों के बीच संवाद के जरिए ऐसा म डल तैयार किया जा सकता है जिसमें निवेश और उद्योग को राहत मिले तथा खनिज–संपन्न राज्यों के वैध राजस्व अधिकार भी सुरक्षित रहें। दुर्भाग्य से संघीय ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर व्यापक राजनीतिक और संस्थागत संवाद की परंपरा कमजोर होती दिखाई दे रही है। एक समय अंतर–राज्यीय परिषद जैसे मंच केंद्र और राज्यों के बीच ऐसे विवादित विषयों पर खुली चर्चा और सहमति बनाने के प्रभावी माध्यम माने जाते थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे संस्थागत मंचों को और अधिक सक्रिय बनाया जाए। केंद्र को यह समझना होगा कि राज्यों की सहमति या कम से कम उनके साथ गंभीर विमर्श केवल राजनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि सहकारी संघवाद की मूल भावना है। खनन क्षेत्र में सुधार आवश्यक हैं। करों का बोझ कम करना, नीतिगत अनिश्चितता समाप्त करना, लाइसेंस और मंजूरी की प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा निवेश का वातावरण बेहतर करना भी जरूरी है। लेकिन सुधार का अर्थ यह नहीं हो सकता कि राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को एक झटके में समाप्त कर दिया जाए। आर्थिक सुधार और संघीय संतुलन के बीच बेहतर सामंजस्य कायम करना ही अधिक दूरदर्शी रास्ता होगा। केंद्र को यह भी देखना होगा कि खनिज संसाधन असीमित नहीं हैं। आज खनिज निकालकर राजस्व अर्जित किया जा सकता है, लेकिन खनन समाप्त होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी बनी रहती है। इसलिए खनिज–संपन्न राज्यों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना उनके विकास और दीर्घकालिक पुनर्वास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मुद्दा केंद्र या राज्यों में से किसी एक के पक्ष में खड़ा होने का नहीं है। सवाल एक ऐसी व्यवस्था बनाने का है जिसमें देश का खनन क्षेत्र तेज गति से विकसित हो, निवेश बढ़े, उद्योग को अनावश्यक कर बोझ से राहत मिले और साथ ही राज्यों की वित्तीय तथा संवैधानिक स्वायत्तता भी सुरक्षित रहे। यदि किसी मौजूदा व्यवस्था में खामियां हैं तो उन्हें संवाद, सहमति और संतुलित सुधार के जरिए दूर किया जाना चाहिए। केंद्र–राज्य संबंधों से जुड़े विषयों पर एकतरफा फैसले दीर्घकाल में किसी के हित में नहीं होते। आज खनिज कराधान का प्रश्न है, कल कोई दूसरा ऐसा विषय हो सकता है जिसमें राज्यों के अधिकार प्रभावित हों। इसलिए इस विधेयक को केवल खनन क्षेत्र के सुधार के नजरिए से नहीं, बल्कि भारतीय संघीय व्यवस्था के व्यापक संदर्भ में देखना होगा। आर्थिक सुधार जरूरी हैं, लेकिन संघीय संतुलन की कीमत पर नहीं। संसद में विधेयक पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, राज्यों को विश्वास में लिया जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के २०२४ के फैसले के संवैधानिक महत्व पर भी गंभीर विमर्श होना चाहिए। देश के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल तभी संभव है जब आर्थिक विकास के साथ संविधान की संघीय भावना और संस्थागत मर्यादाओं का भी समान रूप से सम्मान किया जाए।

घबराइए मत, कराएंगे समस्या का समाधानः योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में सोमवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों की ध्यान से बात सुनी और आत्मीयता से बोले, 'घबराइए मत, आपकी समस्या का समाधान जरूर कराया जाएगा।' जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान करीब २०० लोगों की समस्याएं सुनीं और पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका त्वरित, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निराकरण कराएं। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे। अपनेपन के भाव मे 'कहां से आए हैं, क्या बात है', कहते हुए एक–एक कर सबकी समस्याएं सुनीं। भरोसा दिया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। किसी को भी परेशान होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को

हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। हर बार के जनता दर्शन की तरह सोमवार को भी कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता का अनुरोध लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भरोसा देते हुए कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी, सरकार पर्याप्त आर्थिक सहायता देगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए धनराशि दी जाएगी। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान सोमवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। शिवावतार गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। उन्होंने मंदिर की गोशाला में पहुंचकर गोसेवा की। गोशाला में योगी ने गोवंश को खूब दुलारा और अपने हाथों से उन्हें गुड़ खिलाया।

अतीक के बेटे उमर के काफिले पर टोल न देने और बैरियर तोड़ने का मुकदमा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर के काफिले की गाड़ियों द्वारा नवाबगंज टोल प्लाजा पर टोल टैक्स नहीं देने और बैरियर तोड़कर निकलने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। नवाबगंज टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर जयप्रकाश यादव की तहरीर पर पुलिस ने रविवार देर रात मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, आठ अगस्त को एनएच–१६ स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा पर कंप्यूटर अ परेटर अजीत और हेल्पर अंशुमन शुक्ला ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान अपराह्न करीब ३.५० बजे टोल बूथ संख्या तीन से मोहम्मद उमर पुत्र अतीक अहमद को पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ जेल से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ प्रयागराज लाया जा रहा था। तहरीर के मुताबिक सरकारी वाहनों के पीछे कई अन्य वाहन भी काफिले में चल रहे थे। इनमें सफेद रंग की महिंद्रा एक्सयूवी और काले रंग की क्रेटा समेत करीब २५ से ३० अन्य वाहन शामिल थे। आरोप है कि इन वाहनों ने टोल टैक्स अदा किए बिना तेज रफ्तार में टोल प्लाजा के बूम बैरियर को तोड़कर निकलने का प्रयास किया। टोल कर्मियों द्वारा वाहनों को रोकने का प्रयास किए जाने पर कथित तौर पर उनके साथ गाली–गलौज और धमकी दी गई। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ

वाहनों से टोल कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया, जिस पर कर्मचारियों ने पीछे हटकर अपनी जान बचाई। टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर ने मुकदमे में टोल टैक्स अदा किए बिना निकलने वाले दर्जनों वाहनों के नंबर भी उपलब्ध कराए हैं। तहरीर में सरकारी संपत्ति यानी टोल बैरियर को क्षति पहुंचाने के साथ राजस्व के नुकसान का भी आरोप लगाया गया है। नवाबगंज थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

यूपी टी–२० लीग सीजन–४ का भव्य आगाज आज, सीएम योगी होंगे मुख्य अतिथि

लखनऊ। यूपी टी–२० लीग के चौथे सत्र का आगाज भव्य समारोह के साथ होगा। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने लीग के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन ड. संजय कपूर का निमंत्रण स्वीकार किया है। उद्घाटन समारोह से एक दिन पहले ड. संजय कपूर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान यूपी टी–२० लीग की सभी छह टीमों के कप्तान भी मौजूद रहे। कप्तानों ने मुख्यमंत्री को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें हरसंभव सहयोग का

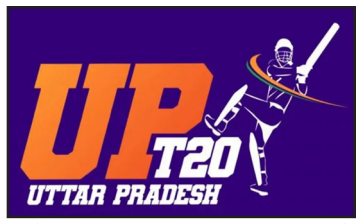

भरोसा दिलाया। सीजन–४ के उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। समारोह में मशहूर गायक शंकर महादेवन और गायिका जैस्मीन सैंडलास लाइव प्रस्तुति देंगी। इसके अलावा ड्रोन शो और लेजर लाइट शो दर्शकों के लिए प्रमुख आकर्षण होंगे। उद्घाटन समारोह के बाद लीग का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इसमें गत चौंपियन काशी रुद्रास का सामना मेरठ मावेरिक्स से होगा। नए सीजन को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में खासा उत्साह है। समारोह में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। यूपी टी–२० लीग गवर्निंग काउंसिल के सदस्य संजीव कुमार सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर नांदेड़ में हमला

नई दिल्ली। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख एवं पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमला किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बादल पर एक गुरुद्वारे के पास हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में

भर्ती कराया गया है। एक वायरल वीडियो में बादल को एक इमारत के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है और उनके दाहिने हाथ पर कपड़ा बंधा हुआ है। इससे पहले दिन में, बादल अकाली दल की सांसद एवं अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल के साथ नांदेड़ स्थित तख्त श्री हजूर साहिब गए थे।

कौशल प्रशिक्षण से रोजगार तकः यूपीएसडीएम और आईआईए के बीच समझौता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ उद्योगों और रोजगार से जोड़ने की दिशा में अहम पहल की गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत पहले चरण में लखनऊ, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमेठी, वाराणसी, एनसीआर और बरेली को शामिल किया गया है। आईआईए की २१८वीं केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में हुए चार महत्वपूर्ण समझौतों में यूपीएसडीएम और आईआईए के बीच हुआ समझौता भी शामिल है। लखनऊ स्थित आईआईए भवन में आयोजित बैठक में १०० से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समझौते के तहत यूपीएसडीएम से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को आईआईए के औद्योगिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। उन्हें अप्रेंटिसशिप, रोजगार, उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव, रोजगार मेलों और प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है। इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण और उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग और आईआईए के बीच भी समझौता हुआ। इसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को आईआईए के चौप्टर नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। आईटीआई विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप, रोजगार, उद्योग भ्रमण, व्यावहारिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञों के व्याख्यान और मार्गदर्शन के अवसर मिलेंगे। आईआईए के रोजगार सेवा पोर्टल के माध्यम से आईटीआई से प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को सदस्य उद्योगों में रोजगार के अवसरों से जोड़ने की व्यवस्था भी की जाएगीयुवाओं को रोजगार के साथ उद्यमिता से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। तीसरे समझौते के तहत नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क और वाधवानी फाउंडेशन के एक्सेलेट कार्यक्रम के साथ आईआईए का सहयोग आगे बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और नए कारोबार को प्रोत्साहित करना है। वहीं, एएफपीओ डेवलपमेंट काउंसिल और आईआईए के बीच हुए चौथे समझौते में उद्यमिता, ग्रामीण औद्योगिकीकरण, निवेश, नवाचार, किसान उत्पादक संगठनों, कौशल विकास, रोजगार और एमएसएमई विकास को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के क्रियान्वयन में भी सहयोग किया जाएगा। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव हरिओम ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में कौशल विकास के लिए बजट, प्रशिक्षण सुविधाओं और संस्थागत ढांचे को लगातार मजबूत किया है। अब प्राथमिकता कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़कर युवाओं के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना है। उन्होंने एमएसएमई से आईटीआई विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराने का आह्वान किया। साथ ही प्रशिक्षण के वित्तीय पक्ष में आवश्यक सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों की साझेदारी युवाओं को वास्तविक रोजगार से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने उत्तर प्रदेश सरकार की कौशल विकास पहलों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार के प्रयास एमएसएमई को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने और प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत–२०४७ के लक्ष्य को हासिल करने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आईआईए सरकार के साथ मिलकर कौशल विकास को उद्योगों की मांग, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। दिनेश गोयल ने चारों समझौतों को सरकार, उद्योग और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की साझेदारी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का व्यावहारिक रोडमैप बताया। बैठक में मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन पुलकित खरे सहित आईआईए के वरिष्ठ पदाधिकारी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, उपाध्यक्ष, चौप्टर चेयरमैन और बड़ी संख्या में उद्योग प्रतिनिधि मौजूद रहे। आईआईए महिला शाखा की चेयरपर्सन आनंदी अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

सीमा पर शांति के बिना चीन से संबंधों में स्थायित्व संभव नहीं

राकेश पाण्डेय 'निश्छल'

भारत–चीन संबंध एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां कूटनीतिक संवाद और आर्थिक सहयोग के साथ–साथ सीमा पर चीन की गतिविधियां गंभीर चिंता का कारण बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने हाल में यह स्पष्ट करके उचित ही किया है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता का "सर्वोच्च" महत्व है। यह बात जितनी सरल है, उसका रणनीतिक महत्व उतना ही गहरा है। आखिर सीमा पर तनाव बना रहे और दूसरी ओर संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश होती रहे, तो यह विरोधाभास लंबे समय तक नहीं चल सकता। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति केवल दो देशों के बीच सामान्य संबंधों की एक शर्त नहीं है, बल्कि पूरे एशियाई क्षेत्र की स्थिरता से भी जुड़ी हुई है। दोनों देश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तियां हैं। ऐसे में सीमा पर होने वाली छोटी–सी घटना भी व्यापक रणनीतिक तनाव का रूप ले सकती है। इसलिए भारत का यह कहना पूरी तरह उचित है कि सीमा पर स्थिति का सीधा असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। हाल में अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने भी चिंता बढ़ाई है। कुछ रील्स में स्थानीय लोग सीमा की सुरक्षा को लेकर भारत की कथित उदासीनता पर सवाल उठाते दिखाई दिए। वहीं कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के ताकसिंग सर्कल में पुकार ला और ओल्लो के निकट वास्तविक नियंत्रण रेखा पार की। ऐसे दावों की आधिकारिक पुष्टि और तथ्यात्मक जांच जरूरी है, लेकिन इस तरह की खबरों का लगातार सामने आना अपने आप में इस बात का संकेत है कि सीमा पर किसी भी प्रकार की ढिलाई की गुंजाइश नहीं हो सकती। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सीमा क्षेत्रों की स्थिति भारत–चीन संबंधों को प्रभावित करेगी और चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ या अतिक्रमण को भारत सबसे गंभीर मुद्दों में मानता है। यह विषय दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत में लगातार उठाया जाता रहा है। लेकिन अब मूल प्रश्न यह है कि भारत की इन आपत्तियों का चीन पर कितना

प्रभाव पड़ रहा है? चीन की रणनीति को केवल उसके आधिकारिक बयानों से समझना पर्याप्त नहीं होगा। चीन की विदेश और सुरक्षा नीति का इतिहास बताता है कि वह सीमा विवादों को केवल कूटनीतिक विषय के रूप में नहीं देखता। सीमा पर दबाव बनाना, रणनीतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करना और बातचीत के साथ जमीन पर अपनी स्थिति बदलने की कोशिश करना उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा रहा है। ऐसे में भारत के लिए केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि सेना और भारत–तिब्बत सीमा पुलिस पूरी तरह सतर्क हैं। सतर्कता जरूरी है, लेकिन उसके साथ स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी जरूरी है। यदि चीन को यह संदेश जाता है कि सीमा पर उसकी गतिविधियों का भारत के साथ आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों पर कोई उल्लेखनीय असर नहीं पड़ेगा, तो उसके व्यवहार में बदलाव की संभावना कम हो सकती है। यही वह बिंदु है जिस पर भारत को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। सीमा पर तनाव के बावजूद यदि द्विपक्षीय व्यापार में चीन से आयात बढ़ता रहता है और चीनी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास आगे बढ़ते हैं, तो चीन के रणनीतिक निर्णयकर्ताओं के लिए यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक होगा कि सीमा विवाद के बावजूद भारत आर्थिक संबंधों को अलग खांचे में रखता है। यह जरूरी नहीं कि भारत चीन के साथ व्यापार पूरी तरह रोक दे या आर्थिक संबंध समाप्त कर दे। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऐसा करना न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यक। लेकिन आर्थिक संबंधों को राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक हितों से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। जहां देश की रणनीतिक और सुरक्षा चिंताएं गंभीर हों, वहां व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग की नीतियों में पर्याप्त सावधानी और रणनीतिक संतुलन होना चाहिए। भारत की चीन नीति में सबसे बड़ी आवश्यकता स्पष्टता की है। पिछले कुछ वर्षों में सीमा पर तनाव, सैन्य तैनाती, कूटनीतिक बातचीत, व्यापारिक निर्भरता और निवेश से जुड़े मुद्दे अलग–अलग स्तरों पर संभाले जाते रहे हैं। अब समय आ गया है कि इन सभी पहलुओं को एक समग्र चीन नीति के भीतर जोड़ा जाए। चीन के साथ संबंध केवल विदेश मंत्रालय का विषय नहीं हो सकते। इसमें रक्षा, वाणिज्य, उद्योग, प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और आंतरिक सुरक्षोंसभी क्षेत्रों की भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन नीति राजनीतिक दलों के तात्कालिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सहमति पर आधारित हो। चीन भारत का पड़ोसी भी है, प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी और गंभीर सामरिक प्रतिस्पर्धी भी। इसलिए उससे न तो भावनात्मक टकराव की नीति कारगर होगी और न ही केवल आर्थिक हितों को प्राथमिकता देने की नीति। भारत को ऐसी व्यावहारिक और दृढ़ रणनीति चाहिए जिसमें संवाद के दरवाजे खुले रहें, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर कोई अस्पष्टता न हो। सीमा पर भारत को अपनी सैन्य और अवसंरचनात्मक क्षमता लगातार मजबूत करनी होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, निगरानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार केवल विकास का कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता है। स्थानीय आबादी का विश्वास और सीमावर्ती क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती नागरिक केवल सीमा के पास रहने वाले लोग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए उनकी शिकायतों और आशंकाओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। साथ ही भारत को चीन के साथ संवाद भी जारी रखना चाहिए। सीमा विवाद का स्थायी समाधान सैन्य तनाव बढ़ाने से नहीं, बल्कि लगातार और ठोस बातचीत से ही संभव है। लेकिन संवाद तभी प्रभावी होता है जब उसके पीछे राष्ट्रीय शक्ति और स्पष्ट रणनीतिक इच्छाशक्ति हो। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि बातचीत और जमीन पर वास्तविक स्थिति के बीच कोई असंतुलन न पैदा हो। चीन की गतिविधियों को केवल एक–दो घटनाओं के संदर्भ में देखने के बजाय दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि से देखना होगा। यदि सीमा पर कोई घटना होती है, तो उसका तत्काल सैन्य और कूटनीतिक उत्तर जरूरी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि ऐसी कार्रवाइयों की लागत चीन के रणनीतिक आकलन में स्पष्ट दिखाई दे। यह लागत सैन्य, कूटनीतिक, आर्थिक या तकनीकी किसी भी रूप में हो सकती है। उद्देश्य टकराव बढ़ाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश चीन के लिए लाभकारी विकल्प न बने। भारत को यह भी समझना होगा कि चीन के साथ संबंधों में केवल प्रतिक्रियात्मक नीति लंबे समय तक काम नहीं करेगी। हर बार किसी घटना के बाद बयान जारी करना और फिर बातचीत की प्रतीक्षा करना पर्याप्त नहीं है। भारत को आने वाले दशक के लिए चीन के संदर्भ में अपनी स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करनी होंगीं। कहां सहयोग करना है, कहां प्रतिस्पर्धा करनी है, किन क्षेत्रों में निर्भरता कम करनी है और किन मामलों में दृढ़ प्रतिरोध करना है। भारत और चीन के संबंधों में स्थिरता की पहली शर्त सीमा पर शांति है। चीन यदि भारत के साथ सामान्य और बेहतर संबंध चाहता है तो उसे सीमा पर ऐसी गतिविधियों से बचना होगा जो अविश्वास को बढ़ाती हैं। दूसरी ओर भारत को भी अपनी कूटनीतिक भाषा के साथ अपनी रणनीतिक कार्रवाई में स्पष्टता दिखानी होगी। अब समय आ गया है कि भारत चीन को लेकर एक ऐसी समग्र, दीर्घकालिक और राष्ट्रीय सहमति पर आधारित नीति तैयार करे, जिसमें सीमा सुरक्षा, आर्थिक हित, व्यापार, निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता और कूटनीतिक संबंध सभी एक–दूसरे से जुड़े हों। चीन के साथ संबंध सामान्य रखना भारत के हित में है, लेकिन सामान्य संबंधों की कीमत राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं हो सकती। सीमा पर शांति और सम्मानजनक यथास्थिति के बिना किसी भी आर्थिक या कूटनीतिक सामान्यीकरण का आधार कमजोर ही रहेगा। चीन से संवाद जरूरी है, लेकिन संवाद की सफलता के लिए सीमा पर ढ़ता भी उतनी ही जरूरी है। भारत की चीन नीति अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि स्पष्ट रणनीति और राष्ट्रीय सहमति से संचालित होनी चाहिए।

लोकसभा ने एफसीआरए संशोधन विधेयक जेपीसी को भेजा

नई दिल्ली। लोकसभा ने विदेशी अनुदान विनियमन संशोधन विधेयक (एफसीआरए), २०२६ को दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव बुधवार को विपक्ष के विरोध के बीच पारित कर दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह विधेयक गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर लाया गया है जिसे संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने पूरी तरह गलत बताया और कहा कि विपक्षी सदस्यों को विधेयक जेपीसी को भेजे जाने का समर्थन करना चाहिए ताकि वहां इस पर व्यापक विचार विमर्श हो सके। विपक्षी सदस्यों के शोर–शराबे के बीच सदन ने प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। प्रस्ताव के अनुसार जेपीसी के लिए लोकसभा के २१ सदस्यों का नामांकन अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के १० सदस्यों का नामांकन सभापति सी पी राधोंष्णन द्वारा किया जाएगा। समिति को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। श्री राय के प्रस्ताव रखते ही विपक्षी सदस्यों ने विधेयक का विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस के के.सी. वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि विधेयक अल्पसंख्यकों और गैर–सरकारी संगठनों को निशाना बनाने वाला है। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि एफसीआरए में प्रस्तावित बदलावों का मकसद अल्पसंख्यकों तथा एनजीओ को निशाना बनाना है। श्री रिजिजू ने विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए श्री अखिलेश यादव को विधेयक में किसी भी 'अल्पसंख्यक विरोधी' प्रावधान को दिखाने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि विधेयक में किसी अल्पसंख्यक या समुदाय को निशाना बनाने वाला एक भी शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष को विधेयक के प्रावधानों पर आपत्ति है तो उसे जेपीसी में भेजा जा रहा है, जहां सदस्यों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। श्री यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष विधेयक के मौजूदा प्रारूप का विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के विधेयक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर लाए जा रहे हैं। श्री रिजिजू ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि विधेयक देश के हर समुदाय की सुरक्षा के लिए है। इससे पहले जैसे ही सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दो बजे दोबारा शुरु हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर से सदन में गृहमंत्री अमित शाह के बयान तथा अन्य मांगों को लेकर भारी हंगामा शुरु कर दिया। पीठासीन जगदम्बिका पाल ने सदन को बताया कि कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव आए हैं, लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला ने इनमें से किसी को स्वीकार नहीं किया है। शोर–शराबे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखे गए। सदन में भारी हंगामे को देखते हुए श्री पाल ने सदन की कार्यवाही तीन बजे तक स्थगित कर दी।

शाह ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में कमाल की चीजें देखने को मिल रही हैं। संसद का सत्र शुरू होने के बाद से ही दोनों सदनों की कार्यवाही से दूर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्र समाप्त होने से एक दिन पहले बुधवार को स्पीकर को चिट्ठी लिखी। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि वे नीट यूजी के पेपर लीक पर छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करें। इससे पहले उन्होंने संसद परिसर में मीडिया से भी कहा कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष और खास कर राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे चर्चा से भाग रहे हैं। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वह संसद चलने दे। शाह ने बुधवार को रहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने दे। अमित शाह ने कहा कि सत्र शुरू होने के बाद से वे हर दिन संसद आ रहे हैं और अपने चौम्बर में मौजूद रहते हैं, लेकिन विपक्ष दोनों सदनों को चलने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि जब संसद की कार्यवाही ही नहीं चलने दी जा रही है तो सदन में जाने का क्या मतलब है। अमित शाह ने बुधवार को कहा, 'अब जनता तय करे कि वास्तव में कौन भाग रहा है। आज दोपहर तीन बजे से कल दोपहर

तीन बजे तक सरकार हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है'। उन्होंने कहा कि वह सदन में मौजूद रहेंगे, सभी की बातें सुनेंगे और हर सवाल का जवाब देंगे। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वह इस मुद्दे पर चर्चा के साथ साथ इस बात पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि विपक्ष चर्चा क्यों नहीं करना चाहता। गौरतलब है कि गुरुवार को संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है। बहरहाल, अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है, 'आप जानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान सरकार की ओर से नीट परीक्षा को लेकर छात्रों के प्रदर्शन पर संसद में चर्चा कराने पर सहमति जताई है'। शाह ने कहा, 'मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विपक्ष की मांग से पहले ही संसद के मौजूदा सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पेश किया गया। उस समय विपक्ष के किसी भी सदस्य ने सदन में नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात नहीं रखी थी। इसके बावजूद सरकार इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा के लिए तैयार है'। उन्होंने लिखा, 'मेरा अनुरोध है कि आप विपक्ष से चर्चा करें और आपसी सहमति के आधार पर आज से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जितना समय, दिन या घंटे उचित समझें, निर्धारित करें'।

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल का अमित शाह पर निशाना

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने शाह के बातचीत के प्रस्ताव पर कहा कि विपक्ष को उनका लेक्चर नहीं सुनना है। राहुल गांधी ने कहा, 'हमें उनका लेक्चर नहीं सुनना है। पहले ये बताएं कि जंतर मंतर पर छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई। उन्होंने आदेश नहीं दिया तो वे इस्तीफा दें'। राहुल ने आगे कहा, 'स्टूडेंट्स को गोली किसने मारी? स्टूडेंट्स को कीलों वाली लाठियों से पीटने का अर्डर किसने दिया? क्या अमित शाह ने हमारे बच्चों को गोली मारने का अर्डर दिया था? अगर उन्होंने दिया है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए'। राहुल ने शाह पर निशाना साधते हुए कहा, 'शाह घर के सामने हजार पुलिस वाले खड़े होते हैं। ३० गाड़ियां उनके आगे पीछे होती हैं कि कहीं कोई बच्चा न आ जाए।

पिछले २० दिनों से अमित शाह गायब हैं। गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है। वह सदन में नहीं आ सकते'। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'विपक्ष ने साफ–साफ कह दिया है कि हमें अमित शाह के भाषण में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मैं 'हम' कहता हूं, तो मेरा मतलब इस देश की युवा पीढ़ी से है'।

यूपी के 8 शहरों के युवाओं के लिए बड़ी पहल, लखनऊ से बरेली–वाराणसी तक खुलेगा रोजगार का नया रास्ता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी और कौशल विकास को लेकर एक अहम पहल हुई है। खास बात यह है कि इसका पहला चरण सीधे लखनऊ, बाराबंकी, मुजफ्फर नगर, मुरादाबाद, अमेठी, वाराणसी, एनसीआर और बरेली से शुरू होगा। यहां कौशल प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को उद्योगों से जोड़ने की तैयारी है। मतलब साफ है। युवा प्रशिक्षण लेगा, उद्योगों का अनुभव हासिल करेगा, अप्रेंटिसशिप करेगा और फिर रोजगार के लिए तैयार होगा। इसी कड़ी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) और इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आइआइए) के बीच समझौता हुआ है। यह समझौता आइआइए की २१८वीं केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में हुए चार महत्वपूर्ण समझौतों में से एक है। बैठक लखनऊ स्थित आइआइए भवन में हुई, जिसमें १०० से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यूपीएसडीएम और आइआइए के बीच हुए समझौते के तहत पहले चरण में लखनऊ, बाराबंकी, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमेठी, वाराणसी, एनसीआर और बरेली को शामिल किया गया है। यहां यूपीएसडीएम से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को आइआइए के औद्योगिक नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। उन्हें अप्रेंटिसशिप, रोजगार, उद्योगों में काम का अनुभव, रोजगार मेले और व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी जिस युवा के पास हुनर है, उसे उद्योगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश

सरकार के प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग और आइआइए के बीच भी समझौता हुआ। इसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) को आइआइए के चौप्टर नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप, रोजगार, उद्योग भ्रमण, व्यावहारिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञों के व्याख्यान और मार्गदर्शन के अवसर मिलेंगे। आइआइए के रोजगार सेवा पोर्टल के माध्यम से आइटीआइ से प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को सदस्य उद्योगों में रोजगार के अवसरों से जोड़ने की भी व्यवस्था की जाएगी। बैठक में रोजगार के साथ युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। तीसरे समझौते के तहत नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क और वाधवानी फाउंडेशन के एक्सेलेरेट कार्यक्रम के साथ आइआइए का सहयोग आगे बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य उद्यमिता प्रशिक्षण और नए कारोबार को प्रोत्साहित करना है। वहीं, एएफपीओ डेवलपमेंट काउंसिल और आइआइए के बीच हुए चौथे समझौते के तहत उद्यमिता, ग्रामीण औद्योगिकी करण, निवेश, नवाचार, किसान उत्पादक संगठनों, कौशल विकास, रोजगार और एमएसएमई विकास को बढ़ावा देने पर काम होगा। इसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के क्रियान्वयन में भी सहयोग किया जाएगा। मुख्य अतिथि हरिओम, आइएएस, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में कौशल विकास के लिए बजट, प्रशिक्षण सुविधाओं और संस्थागत ढांचे को लगातार मजबूत किया है। अब प्राथमिकता कौशल प्रशिक्षण को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों से जोड़कर युवाओं के लिए सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सुनिश्चित करना है। उन्होंने एमएसएमई से आइटीआइ विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के अवसर देने का आह्वान किया। साथ ही प्रशिक्षण के वित्तीय पक्ष में आवश्यक सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों और प्रशिक्षण संस्थानों की साझेदारी युवाओं को वास्तविक रोजगार से जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। आइआइए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने उत्तर प्रदेश सरकार की कौशल विकास पहलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयास एमएसएमई को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने और प्रदेश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत २०४७ के लक्ष्य को हासिल करने में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइआइए सरकार के साथ मिलकर कौशल विकास को उद्योगों की मांग, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और रोजगार से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। दिनेश गोयल ने चारों समझौतों को सरकार, उद्योग और कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की साझेदारी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का व्यावहारिक रोडमैप बताया। यूपी के युवाओं के लिए इस पहल की सबसे बड़ी बात यह है कि कौशल प्रशिक्षण को सीधे उद्योग और रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले चरण में शामिल आठ क्षेत्र प्रदेश के अलग–अलग हिस्सों में मौजूद युवाओं को इस व्यवस्था से जोड़ने का आधार बन सकते हैं। बैठक में मुख्य अतिथि हरिओम, आइएएस, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलकित खरे, आइएएस, मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मौजूद रहे। आइआइए की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक अग्रवाल, महासचिव दीपक बजाज, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश के. अग्रवाल और इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट नीरज सिंघल उपस्थित रहे। इसके अलावा आइआइए के अनेक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, उपाध्यक्ष, चौप्टर चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योग प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया। अंत में आइआइए महिला शाखा की चेयरपर्सन आनंदी अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

होर्मुज पर अमेरिका का पूरा कब्जाः ट्रंप

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान पर भरोसा नहीं करते हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। श्री ट्रंप ने यहां संवाददाताओं से कहा मुझे ईरान पर भरोसा नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे ईरान पर भरोसा है? मुझे ईरान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ईरानी पक्ष ने हमेशा झूठ बोला है। श्री ट्रंप ने होर्मुज पर नियंत्रण का दावा करते हुए कहा कि अगर ईरान स्थिति बदलने की कोशिश करता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा होर्मुज जलडमरूमध्य पर हमारा पूरा नियंत्रण है। उनका इसपर कोई नियंत्रण नहीं। हम उसे चला रहे हैं। अगर ईरान कभी कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे 'उड़ा दिया' जायेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस समय मजबूत स्थिति में है और दावा किया कि ईरान ने क्षेत्र में अपना पिछला प्रभाव खो दिया है। उन्होंने कहा अभी हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हमारे सामने एक ऐसा देश है जो ५० वर्षों से मध्य पूर्व में दबंग बना हुआ था अब वह पश्चिम एशिया का दबंग नहीं रहा। गौरतलब है कि फरवरी के अंत में अमेरिका–इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के

बाद क्षेत्र में जारी तनाव के बीच उनकी इस तरह की टिप्पणियां आई हैं। अमेरिका और ईरान अब तक टकराव खत्म करने के लिए किसी अंतिम समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं, जबकि होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास जारी व्यवधानों से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर खतरा बना हुआ है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जहां से सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के एक बड़े हिस्से की कच्चे तेल और तरलीत प्रोतिक गैस की आपूर्ति गुजरती है। ईरान के सरकारी प्रसारक प्रेस टीवी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के हवाले से कहा है कि २८ फरवरी, २०२६ तक यह जलमार्ग खुला रहा था। उन्होंने पश्चिमी प्रतिबंधों की भी आलोचना की। श्री बघाई ने कहा यह नहीं भूलना चाहिए कि होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की स्थिति और उसके साथ जो कुछ हुआ, वह अमेरिका और इजरायली शासन की सैन्य आक्रामकता के कारण हुआ है, जो अब भी जारी है। जहां तक ईरान द्वारा शर्तें रखे जाने के दावों का सवाल है, उन्हें यह मामला अपनी ही सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। रणनीतिक जलमार्ग को लेकर तनाव अब भी संघर्ष का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस बीच, तेहरान और ओमान के बीच इस महत्वपूर्ण जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत जारी है।

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! सर्किल रेट में ४८ः तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव

अमरोहा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना और इसके हरिद्वार तक प्रस्तावित विस्तार को गति देने के उद्देश्य से अमरोहा जिला प्रशासन ने भूमि के नए सर्किल रेट प्रस्तावित किए हैं। एक्सप्रेसवे से प्रभावित राजस्व ग्रामों में सर्किल रेट में अधिकतम ४८ प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे किसानों को उनकी भूमि का बेहतर मूल्य मिलने के साथ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी गति मिलने की उम्मीद है। जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ द्वारा जारी प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाले गांवों में वर्तमान सर्किल दरों की असमानता को दूर करते हुए आसपास के गांवों के समतुल्य दरें निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत कई गांवों में सर्किल रेट में ४८ प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा तहसील हसनपुर क्षेत्र में एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन से सटी कृषि भूमि के लिए भी नई दरें प्रस्तावित की गई हैं। प्रशासन ने जिले के अन्य क्षेत्रों में भी भूमि मूल्यांकन में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में १० प्रतिशत, विकासशील क्षेत्रों में १५ प्रतिशत तथा नगरीय, अर्धनगरीय एवं लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों में २० प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों से जुड़े गांवों में भूमि मूल्यों में पांच से २० प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जबकि कुछ ऐसे गांव जहां दरों में अत्यधिक असमानता थी, वहां ३० प्रतिशत तक वृद्धि कर संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है। कृषि भूमि के लिए बेल्टिंग प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में क्षेत्र के किसानों ने अपनी भूमि के उचित मूल्य की मांग को लेकर भाजपा विधायक राजीव तरारा से मुलाकात की थी। विधायक ने किसानों की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद प्रशासन द्वारा सर्किल रेट में वृद्धि का प्रस्ताव सामने आया है। प्रशासन का मानना है कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं कम होंगी और गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना निर्धारित समय में पूरी करने में मदद मिलेगी। इससे भविष्य में हरिद्वार तक सीधी और सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली के तहत प्रस्तावित दरों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची की प्रतियां अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सहायक महानिरीक्षक निबंधन, संबंधित उप जिलाधिकारियों, उप निबंधक कार्यालयों तथा एनआईसी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं। इच्छुक व्यक्ति १४ अगस्त से २५ अगस्त की शाम पांच बजे तक अपनी आपत्तियां और सुझाव लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण एक से तीन सितंबर के बीच किया जाएगा।

झारखंड भर्ती परीक्षाओं के अनियमितता के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी

नई दिल्ली। झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को २०वें दिन भी जारी है। वहीं, प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन

वापस लेने से इनकार कर दिया है। 'जेपीएससी–जेएसएससी रिफ र्म्स मंच' के बैनर तले अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भर्ती परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता, कई परीक्षाओं को रद्द करने और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या झारखंड के बाहर के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति से पूरे प्रकरण की स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के नेता रघुबर दास ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते के भीतर सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं हुई तो वह अनशन करेंगे। वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी)ने इस मुद्दे पर १,२०० से अधिक विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। दास ने २०२४ में आबकारी आरक्षक भर्ती की शारीरिक परीक्षा के दौरान कथित तौर पर जान गंवाने वाले १६ अभ्यर्थियों के प्ररिवारों को एक–एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने की मांग की। एबीवीपी नेताओं ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी)की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और इसके गठन में बार–बार किए गए बदलावों का हवाला दिया है। झारखंड में मुख्य विपक्षी भाजपा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर आंदोलन को दबाने का आरोप लगाया है। सोरेन सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भाजपा पर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण करने की आलोचना की और दावा किया कि राज्य की विपक्षी पार्टी ने विरोध प्रदर्शनों में बाधा डालने के लिए बाहर से कार्यकर्ताओं को बुलाया है। विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सोमवार को हुए टकराव के बाद तनाव बढ़ गया क्योंकि सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर–बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया, पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े। भाजपा ने इसके बाद पुलिस की कार्रवाई के विरोध में राज्यव्यापी बंद का आयोजन किया। इस बीच, अनशन कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने रांची के सिविल सर्जन से विरोध स्थल पर लौटने की अनुमति मांगी। महतो ने कहा कि उनकी 'आत्मा' छात्रों के आंदोलन के साथ ही है। अनशन कर रहे चार अन्य छात्रों को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले, सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच बातचीत के छह दौर गतिरोध को खत्म करने में नाकाम रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार भर्ती परीक्षा में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदर्शन कारियों को भरोसा दिलाया कि १४वीं झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी)परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने साथ ही भाजपा पर राजनीतिक फायदे के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया।

93 वर्ष की हुईं वैजयंती माला

बॉलीवुड की जानी–मानी अभिनेत्री वैजयंती माला आज ६३ वर्ष की हो गईं।तमिलनाडु में १३ अगस्त १६३३ को जन्मीं वैजयंती माला ने अपने सिने करियर की शुरुआत महज १६ वर्ष की उम्र में एक तमिल फिल्म से की। वर्ष १६५१ में प्रदर्शित फिल्म 'बहार' से वैजयंती माला ने बॉलीवुड में पदार्पण किया। वर्ष १६५४ में प्रदर्शित फिल्म 'नागिन' उनके सिने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई। वर्ष १६५५ में प्रदर्शित फिल्म 'देवदास' वैजयंती माला के सिने करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार की जाती है। विमल राय के निर्देशन में शरतचंद्र के उपन्यास पर बनी इस फिल्म में वैजयंती माला ने चंद्रमुखी के किरदार को रुपहले पर्दे पर साकार किया। इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए वह सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार से सम्मानित की गईं। वर्ष १६५८ में प्रदर्शित फिल्म 'साधना' वैजयंती माला के करियर की महत्वपूर्ण फिल्मों में शुमार है। बी.आर. चोपड़ा निर्मित–निर्देशित इस फिल्म में वैजयंती माला अपने करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त करने में सफल रहीं। वर्ष १६५८ में ही प्रदर्शित फिल्म 'मधुमती' वैजयंती माला के करियर की एक और उल्लेखनीय फिल्म साबित हुई। विमल राय निर्मित यह फिल्म पुनर्जन्म पर आधारित थी। इस फिल्म में वैजयंती माला ने

तिहरी भूमिका निभाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। अपने दमदार अभिनय के लिए वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की गईं। वर्ष १६६४ में प्रदर्शित फिल्म 'संगम' वैजयंती माला के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। राज कपूर निर्मित–निर्देशित 'संगम' त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित थी। इस फिल्म में उनकी जोड़ी राज कपूर और राजेंद्र कुमार के साथ सराही गई। फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए वैजयंती माला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार से भी सम्मानित की गईं। वैजयंती माला ने अपने करियर के दौरान सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया। इनमें दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त शामिल हैं। वैजयंती माला की जोड़ी सर्वाधिक राजेंद्र कुमार के साथ पसंद की गई। उन्होंने वर्ष १६६८ में डॉ. चमनलाल बाली से शादी कर ली और इसके बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। वर्ष १६६६ में उनकी अंतिम फिल्म 'प्रिंस' प्रदर्शित हुई। वैजयंती माला ने अपने करियर में हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल और बंगाली फिल्मों में भी अभिनय किया। भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। फिल्मों में कई यादगार भूमिकाएं निभाने के बाद वैजयंती माला ने समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया और लोकसभा की सदस्य बनीं। वैजयंती माला इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय नहीं हैं।

पुरानी ईंटों से बना रहे थे नई बाउंड्रीय सीडीओ अभिषेक कुमार ने मारा छापा, गुणवताविहीन निर्माण पर लगाई फटकार

लखीमपुर खीरी। विकास कार्यों में मनमानी और गुणवत्ता से खिलवाड़ पर सीडीओ अभिषेक कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को

मितौली विकासखंड के पीएमश्री विद्यालय रतहरी में बाउंड्रीवाल निर्माण का मामला सामने आने पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान बाउंड्रीवाल में पुरानी ईंटों का प्रयोग मिला। दीवार पर साथ–साथ प्लास्टर भी कराया जा रहा था। निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग देख सीडीओ ने मौके पर ही कड़ी नाराजगी जताई और जिम्मेदारों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्माण की प्रक्रिया और गुणवत्ता की जानकारी ली। निरीक्षण में पाया गया कि दीवार में पुरानी ईंटें लगाई जा रही थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीडीओ ने कंसलटिंग इंजीनियर और ग्राम पंचायत अधिकारी को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। वहीं निर्माण कार्य की प्रभावी निगरानी न किए जाने पर सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के प्रति भी नाराजगी जताई। उन्होंने एडीओ पंचायत से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए। सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि सरकारी धन से कराए जा रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और प्रक्रिया के अनुसार ही कराए जाएं। लापरवाही या अनियमितता मिलने पर संबंधित के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

पत्रकार के साथ जानकी अस्पताल में मारपीट लाठी डंडों से किया हमला, केस दर्ज

लखीमपुर खीरी। कोतवाली सदर इलाके में स्थित जानकी अस्पताल में विज्ञापन के सिलसिले में गए एक स्थानीय पत्रकार के साथ अस्पताल स्टाफ और चिकित्सकों द्वारा कथित तौर पर गाली–गलौज और लाठी–डंडों से गंभीर मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस की धारा ११५(२) ३५१,३५२(२) के अंतर्गत मुकदमा संख्या ०६५२१०२०२६ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रकाश नगर फतेहपुर–सैंधरी के रहने वाले पत्रकार आशीष गुप्ता पुत्र विनोद कुमार गुप्ता ११ अगस्त को शाम करीब ७रू३० बजे जानकी अस्पताल गए थे। वहां उन्होंने अस्पताल में मौजूद महिला चिकित्सक को अपना परिचय दिया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई संदेश विज्ञापन जारी करने के संबंध में बात की।आरोप है कि विज्ञापन की बात सुनते ही महिला चिकित्सक अचानक भड़क गईं और पत्रकार के साथ गाली–गलौज करने लगीं। जब पत्रकार ने इसका विरोध किया, तो वहां मौजूद अन्य चिकित्सकों और अस्पताल के स्टाफ ने उन पर लाठी–डंडों से हमला कर दिया। इस मारपीट में पत्रकार आशीष गुप्ता को शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित का आरोप है कि जब वह नीचे गिर गए, तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।सदर कोतवाली पुलिस ने पीड़ित पत्रकार की तहरीर पर मामला पंजीत कर लिया है। इस मामले की जांच उपनिरीक्षक (अवर निरीक्षक) धर्मेंद्र बहादुर सिंह को सौंपी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की पूरी गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हर–हर महादेव के जयकारों के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रवाना हुए डॉ. आशुतोष गुप्ता

गोला खीरी। भोलेनाथ के अनन्य भक्त और छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ के सुप्रसिद्ध आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. आशुतोष गुप्ता एक बार फिर पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। डॉ. गुप्ता की यह दूसरी कैलाश मानसरोवर यात्रा है। उनके प्रस्थान से पूर्व क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और इष्ट मित्रों ने 'हर–हर महादेव' के गगनभेदी जयकारों, मंत्रोच्चार और पुष्पवर्षा के बीच उन्हें उत्साहपूर्वक विदाई दी और उनकी सुरक्षित व सुखद यात्रा की कामना की। भव्य विदाई समारोह में उमड़े नगर के गणमान्य लोग काठमांडू मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर की इस कठिन और पवित्र यात्रा पर जा रहे डॉ. आशुतोष गुप्ता को विदा करने के लिए गोला गोकर्णनाथ में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष विजय शंकर शुक्ला 'रिंकू' और रोटरी क्लब के अध्यक्ष पंकज पुरवार ने उन्हें पटका और पुष्पहार पहनाकर सम्मानित किया। पंडित लवकुश अवस्थी की अगुवाई में विद्वान ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार कर यात्रा की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया।इस अवसर पर पिंटू शुक्ला, संजय सैनी, गौरव ज्ञान त्रिपाठी, राम मोहन गुप्त, कपिल पुरवार, गौरव गुप्ता, शकुंतला गुप्ता, अर्चना गुप्ता, पूजा पुरवार, डॅ. ए.पी. सक्सेना, गौरी शंकर पाण्डेय, आशीष गुप्ता, मनोज कश्यप और राघवेन्द्र वर्मा आदि ने डॉ. गुप्ता को शुभकामनाएं देकर विदा किया। लखीमपुर एलआरपी बाईपास पर भी हुआ जोरदार स्वागत गोला से प्रस्थान करने के बाद लखीमपुर एलआरपी बाईपास पर भी डॉ. आशुतोष गुप्ता का जोरदार स्वागत किया गया। यहाँ उपस्थित सभासद अजय गुप्ता 'लकी', समाजसेवी आशीष गुप्ता 'कफारा वाले', रूपम गुप्ता श्सोनीश, राज गुप्ता 'पिंकू', अरुण कुमार गुप्ता और राजेश आदि ने डॉ. आशुतोष को पटका पहनाकर अपनी निज शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं प्रेषित कीं।शुभचिंतकों में भारी उत्साहड . आशुतोष गुप्ता के इस पावन सफर पर रवाना होने के समय उनके प्रस्थान पूर्व हर्षोल्लास व्यक्त करने और शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर संजीव दीक्षित, रवींद्र कटियार, योगेश कन्नौजिया, मोहम्मद कामरान, सुधीर कुमार शुक्ला, निशू गुप्ता, सुधीर, नवीन, अभिषेक, बृजेश, रितेश पुरवार, राहुल, जयदेवी, कोमल, सुमन सहित भारी संख्या में स्थानीय नागरिक और शुभचिंतक मौजूद रहे। पूरा माहौल शिव भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया।

ऐतिहासिक देवकली तीर्थ में १७ अगस्त को होगा कालसर्प योग शान्ति महायज्ञ, रजिस्ट्रेशन शुरू

लखीमपुर–खीरी।ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व से जुड़े देवकली तीर्थ स्थल पर आगामी १७ अगस्त २०२६, दिन सोमवार (श्रावण शुक्ल पंचमी यानी श्रीनाग पंचमी) को एक विशाल सामूहिक कालसर्प योग शान्ति महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है।श्रीमती चन्द्रकला आश्रमध्संर्स्त विद्यापीठ के महन्त प्रमोद जी महाराज ने बताया कि कुंडली में कालसर्प दोष होने से व्यक्ति के विकास के सभी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा जातक अपने दैनिक जीवन में मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं से घिरा रहता है। महन्त जी के अनुसार, कालसर्प योग मुख्य रूप से १२ प्रकार का होता है, जबकि इसके विभिन्न आंशिक रूपों को मिलाकर कुल ३,४५६ प्रकार के योग बनते हैं। जीवन में अर्थ, ध र्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दोष का निवारण करवाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। देवकली तीर्थ स्थल राजा जनमेजय के ऐतिहासिक सर्प यज्ञ की पावन धरोहर है। यह देव तीर्थ गोदावरी नदी के पावन जल सहित समस्त पवित्र तीर्थों के जल से प्रतिष्ठित है। साथ ही, यह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सहित द्वादश ज्योतिर्लिंगों की आध यात्मिक ऊर्जा से विभूषित है। यही कारण है कि इस स्थान को कालसर्प योग शांति अनुष्ठान के लिए देश के सर्वोत्तम और सबसे फलदायी स्थानों में से एक माना जाता है। महायज्ञ के भव्य आयोजन को देखते हुए तैयारियाँ जोर–शोर से शुरू कर दी गई हैं। आश्रम प्रशासन ने अपील की है कि जिन भी श्रद्धालुओं की कुंडली में यह दोष है, वे जल्द से जल्द आश्रम कार्यालय से संपर्क कर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवा लें, ताकि समय पर पूजा की व्यवस्था की जा सके।

लापता महिला का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग

लखीमपुर खीरी। लापता महिला का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग , महिला के बेटे ने गुरजंट सिंह निवासी पटेहरा मन्दिर थाना व

जिला खीरी ने ११ अगस्त को थाने पर जाकर लापता होने की लिखित तहरीर दी। गुरजंट सिंह ने बताया कि मेरी मां रजवन्त कोर पत्नी धीर सिह निवासी उपरोक्त का इलाज मानसिक बीमारी का चाल रहा है दिनॉक ११ अगस्त २०२६ को सुबह करीब रू्दन्न बजे बिस्तर से उठ कर कही चली गई हैं काफी खोज बिन किया परंतु कहीं पता नहीं चला सका है। महिला का रंग गेहुँआ रंग इकहारा बदन लम्बाई ५रू३० फिट उम्र करीब ६२ वर्ष है एवं पहनावा आसमानी कलर का सूट सलवार पहने हुए हैं एवं पैरों में चप्पल नहीं है।अगर किसी को इन के बारे में कोई जानकारी मिले तो कृपया इस नम्बर ६६६६७०६२८४ पर संपर्क कर सूचना दें।

ग्रामीणों का विश्वास और सहयोग लिखेगा भविष्य के विकास की पटकथा, ड क्टर कौशल वर्मा, गुजारा,जौहरा, रूरा, अलीगंज में किया जनसम्पर्क

गोला गोकर्णनाथ खीरी। १३६ गोला विधानसभा क्षेत्र में सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से क्षेत्र के भ्रमण पर निकले सनशाइन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के संचालक एवं भाजपा नेता डॉक्टर कौशल वर्मा ने बिजुआ इलाके के गांव गुजारा,जौहरा, रूरा, अलीगंज में ग्रामीणों से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान स्थानीय एवं क्षेत्रीय समस्याओं जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की,गांव स्तर पर डॉक्टर को अपने बीच पाकर ग्रामीणों ने उनको जमीन से जुड़े कुशल मसीहा के रूप में स्वीकार किया। डॉक्टर ने अपना स्नेह विश्वास और आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि ग्रामीणों का मिल रहा विश्वास और सहयोग भविष्य के विकास की लिखेगा पट कथा। बिजली,पानी,सड़क,

चिकित्सा जैसी बुनियादी विकास से जुड़े विभिन्न विषयों व जनकल्याण के मुद्दों पर सुझाव साझा किये। उन्होंने अवसरवादी राजनीति को पीछे छोड़ते हुए शहर के लग्जरी जीवन से निकलकर शहर की तंग गलियों और गांव के गलियारों पर दस्तक देना ही अपनी सच्ची सेवा का हिस्सा माना है। उनका कारवां दिनों दिन बढ़ रहा है। डॉक्टर के द्वारा वर्षों से शोषित पीड़ित वंचित के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों से उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। सेवा को अपना कर्तव्य बताते हुए वंचितों की आवाज बनकर काम करने का संकल्प लिया है। इस मौके पर सम्मानित ग्रामीण जन एवं ड क्टर टीम के लोग मौजूद रहे।

मासिक धर्म के कारण बेटियों की पढ़ाई न रुके, ७५ जिलों में तैयार होंगे २२३ मास्टर ट्रेनर

लखनऊ। बेटियों की शिक्षा मासिक धर्म के कारण बाधित न हो, इसके लिए योगी सरकार विद्यालयों में मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ शिक्षकों को भी संवेदनशील बना रही है। प्रदेश के सभी ७५ जिलों में २२३ मास्टर ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं, जो आगे सभी विद्यालयों के महिला एवं पुरुष शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे। राज्य स्तरीय दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले से प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। १३ अगस्त को ३७ जिलों के १११ प्रतिभागियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, जबकि शेष ११२ प्रतिभागियों को १४ अगस्त को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में मासिक धर्म स्वास्थ्य को केवल सैनिटरी पैड की उपलब्धता तक सीमित नहीं रखा गया है। इसमें विद्यालयों में स्वच्छ एवं सुरक्षित शौचालय, पर्याप्त पानी, साबुन, गोपनीयता, सैनिटरी सामग्री के सुरक्षित निस्तारण और आपात स्थिति में सहायता जैसी व्यवस्थाओं

पर भी जोर दिया जा रहा है। बालिकाओं के लिए अलग और सुरक्षित शौचालय तथा निःशुल्क सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षकों को मासिक धर्म को सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में समझाने, इससे जुड़े मिथकों और झिझक को दूर करने तथा बालिकाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर अपने–अपने जिलों में सभी विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देंगे। इससे राज्य स्तर पर तैयार प्रशिक्षण सामग्री और जानकारी सीधे विद्यालयों तक पहुंच सकेगी। यह पहल बालिकाओं की गरिमा, गोपनीयता और समानता के साथ उनके शिक्षा के अधिकार से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा और गरिमा से जुड़े विषयों को संवेदनशीलता के साथ विद्यालयों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रत्येक मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्रशिक्षण को प्रदेश के सभी विद्यालयों तक पहुंचाया जाएगा।

अक्षय कुमार ने 'हैवान' में निभाया खलनायक का किरदार

मुम्बई। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म 'हैवान' का टीजर रिलीज हो गया है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में अक्षय कुमार पहली बार पूरी तरह नकारात्मक किरदार में नजर आएंगे। टीजर में

अक्षय कुमार का खौफनाक और इंटेंस अंदाज देखने को मिला है। बीनी पहने उनका लुक फिल्म में उनके किरदार के अलग अंदाज की झलक देता है। अक्षय कुमार ने अपने किरदार के बारे में कहा जैसा कि फिल्म का नाम है, मैं 'हैवान' का किरदार निभा रहा हूं और मेरे किरदार में कोई ग्रे शेड नहीं है। वह पूरी तरह से बुरा है। मैं हमेशा से पर्दे पर एक साइको का किरदार निभाना चाहता था।" उन्होंने कहा, "पिछली चार–पांच फिल्मों में मैंने अलग–अलग ज नर के किरदार निभाने की कोशिश की है,क मेडी, ह रर, एक्शन और ड्रामा। लेकिन यह पहली बार है जब मैं पूरी तरह से बुरे किरदार में नजर आऊंगा। मुझे लगातार खुद को चुनौती देना पसंद है और 'हैवान' मेरे लिए वही चुनौती है। निर्देशक प्रियदर्शन ने बताया कि 'हैवान' के लिये अक्षय कुमार को नकारात्मक भूमिका में लेने का विचार कैसे आया। उन्होंने कहा कि 'भूत बंगला' के सेट पर उन्होंने अक्षय को बीनी पहने देखा था और उनका लुक उन्हें पसंद आया। प्रियदर्शन के अनुसार, जब उन्होंने 'हैवान' की कहानी पर काम किया, तब उन्होंने अक्षय को नकारात्मक किरदार में लेने के बारे में नहीं सोचा था। बाद में अक्षय ने खुद उनसे पूछा कि क्या वह यह भूमिका कर सकते हैं, जिस पर प्रियदर्शन हैरान रह गये। प्रियदर्शन ने कहा कि नकारात्मक किरदार में अक्षय कुमार को देखना दर्शकों के लिये अलग अनुभव होगा और इससे अभिनेता की क्षमता को नये अंदाज में देखने का मौका मिलेगा। 'हैवान' में अक्षय कुमार और सैफ अली खान नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया पर आधारित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर है। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी 'हैवान' ११ सितंबर २०२६ को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शौरा ने बटोरी सुर्खियां

बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाटक 'नकाब' को अमेरिका दौरे के दौरान दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली। इस दौरे को नवाजुद्दीन और उनकी बेटी शौरा सिद्दीकी के लिए खास माना जा रहा है। जहां नवाजुद्दीन ने अपनी दमदार प्रस्तुति से दर्शकों को प्रभावित किया, वहीं शौरा ने रंगमंच पर अपनी पहली प्रस्तुति से खूब तारीफ बटोरी। अलग–अलग शहरों में हुए कार्यक्रमों के दौरान दर्शकों ने शौरा की प्रस्तुति की जमकर सराहना की। कई दर्शकों ने उन्हें "शो की जान" बताया, जबकि कुछ ने उनकी प्रस्तुति को शानदार और प्रभावशाली करार दिया। दर्शकों के बीच शौरा के अभिनय को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। पूरे दौरे के दौरान शौरा की तारीफ का सिलसिला जारी रहा। एक दर्शक ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जबकि दूसरे ने

कहा कि वे शौरा को और देखना चाहते थे। उनकी पहली रंगमंचीय प्रस्तुति को लेकर दर्शकों ने गर्व और खुशी भी जाहिर की। शौरा के लिए यह रंगमंच की दुनिया में एक महत्वपूर्ण शुरुआत रही। वहीं, नवाजुद्दीन के लिए भी यह दौरा यादगार अनुभव बन गया। पिता–बेटी की जोड़ी को एक साथ मंच पर देखने का मौका दर्शकों के लिए भी खास रहा। अपने अमेरिका दौरे के अनुभव को साझा करते हुए नवाजुद्दीन ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "यह एक शानदार अनुभव रहा है। इस सफर में मैंने बहुत कुछ सीखा और खोजा। लोगों के इतने प्यार और हमारे शो को सफल बनाने के लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। हमारी टीम से जुड़े सभी लोगों को बहुत–बहुत धन्यवाद।" नवाजुद्दीन की दमदार रंगमंचीय प्रस्तुति और शौरा की शानदार शुरुआत ने 'नकाब' को यादगार बना दिया। अमेरिका में दर्शकों से मिली सराहना ने पिता–बेटी की इस जोड़ी के लिए इस सफर को और खास बना दिया है।

वेलनेस सिटी में १० एकड़ से अधिक भूमि देने वाले किसानों को ग्रीन क रिडोर के पास मिलेंगे भूखंड

लखनऊ। एलडीए की वेलनेस सिटी योजना में लैंड पूलिंग के माध्यम से १० एकड़ से अधिक भूमि देने वाले काश्तकारों को ग्रीन क रिडोर के पास बेहद प्राइम लोकेशन पर भूखण्ड आवंटित किये जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने गुरूवार को योजना का निरीक्षण करके ग्रीन क रिडोर के पास की भूमि को इसके लिए आरक्षित करने के निर्देश दिये हैं। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सुलतानपुर रोड व किसान पथ के मध्य ४८५ हेक्टेयर क्षेत्रफल में वेलनेस सिटी योजना विकसित की जा रही है। जिसके लिए ग्राम–बक्कास, मलूकपुर ढ़कवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा तथा मस्तेमऊ की भूमि चिन्हित है। वेलनेस सिटी को मेडी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ विपासना केन्द्र व मेडिटेशन सेंटर आदि होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लैंड पूलिंग के माध्यम से भूमि जुटाव का कार्य किया जा रहा है। अभी तक लगभग २०० हेक्टेयर भूमि के लैंड पूलिंग के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जोकि योजना के लिए काफी सकारात्मक है। प्रथम चरण में लॉटरी के माध्यम से काश्तकारों को १२५ विकसित भूखण्ड आवंटित किये जा चुके हैं। अगले महीने पुनः ल टरी के माध्यम से लगभग २०० भूखण्ड आवंटित किये जाएंगे। उपाध्यक्ष ने बताया कि लैंड पूलिंग नीति के तहत योजना के लिए १० एकड़ अथवा उससे अधिक भूमि देने वाले किसानों को ५० प्रतिशत अविकसित भूखण्ड ग्रीन क रिडोर के पास आवंटित किये जाएंगे। इसमें भूखण्ड के आसपास वाह्य विकास का पूरा कार्य एलडीए द्वारा कराया जाएगा। उपाध्यक्ष ने बताया कि वेलनेस सिटी के ४ मुख्य मार्गों को निर्माणाधीन ग्रीन क रिडोर से जोड़ा जाएगा। शहीद पथ से किसान पथ के मध्य ६.५ किलोमीटर लंबा व २४ मीटर चौड़ा ग्रीन कॉरिडोर अब आकार लेने लगा है। उन्होंने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से महज ०.५ किलोमीटर की दूरी पर प्रस्तावित वेलनेस सिटी में ट्रैफिक निर्बाद्ध रूप से संचालित हो, इसके लिए योजना में ६० मीटर से २४ मीटर चौड़ी सड़कें विकसित की जा रही हैं। सीजी सिटी योजना में अर्बन वेट लैंड के पास निर्मित फुटओवर ब्रिज एरिया में कार्निवल ३६५ विकसित किया जा रहा है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने परियोजना का निरीक्षण करके ०२ माह में स्थल संचालित करने के निर्देश दिये हैं। यहां १० फूड किय स्क, बच्चों के लिए इनडोर एवं आउटडोर गेम्स, झूले आदि की सुविधा होगी। साथ ही वेट लैंड में आने वाले प्रवासी पक्षियों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है। सीजी सिटी में लगभग ४० करोड़ रूपये की लागत से १५०० मीटर लंबा ब क्स ड्रेन नाला निर्मित किया जा रहा है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178

Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक